राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो दशक बिताने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं मिताली राज

>> 14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 122

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 10 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

प्लास्टिक से पीछा छुड़ाने के तरीके बता रहा स्टार्टअप

नई दिल्ली : प्लास्टिक से पीछा छुड़ाने की मुहिम तेजी से रंग ला रही है। वैकल्पिक उत्पाद बना रहे यंग स्टार्टअप यूनीको की सफलता इसका प्रमाण है। 50 हजार की लागत से शुरू हुआ यह स्टार्टअप महज एक साल में 35 लाख की पूंजी तक पहुंच गया है। (पेज-10)

जागरण विशेष

5जी के स्वागत को तैयार है दमदार स्वदेशी एंटीना

धनबाद : आइआइटी आइएसएम, धनबाद ने अत्याधुनिक 5जी एंटीना तैयार किया है, जो फरवरी तक सरकार को सौंप दिया जाएगा। एंटीना की फ्रीक्वेंसी शानदार है और बैट्री लाइफ पांच गुना अधिक, आकार और वजन 4जी एंटीना के बराबर ही है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

भारत और फ्रांस में मजबूत हुए रक्षा संबंध : राजनाथ

पेरिस : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को बताया कि उन्होंने फ्रांस दौरे के क्रम में बुधवार को अपने फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली के साथ उपयोगी बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के सभी आयामों की समीक्षा की।

महासमर ▶ पृष्ठ 4

2024 तक सभी घुसपैठिये देश से बाहर होंगे : शाह

कैथल : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को हरियाणा में रैलियां कर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का शंखनाद किया। कैथल में आयोजित विजय संकल्प रैली के दौरान उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी घुसपैठियों को देश से बाहर करने का एलान किया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

एक माह की देरी से शुरू हुई मानसून की वापसी

नई दिल्ली : दक्षिणी पश्चिम मानसून ने चार महीने बरसात के बाद बुधवार से अपनी वापसी शुरू कर दी। वैसे मानसून की विदाई की सामान्य तारीख एक सितंबर थी। मौसम विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी।

कारोबार ▶ पृष्ठ 12

हाईवे किनारे की जमीन से पैसे जुटाएगा एनएचएआइ

नई दिल्ली : नई परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए एनएचएआइ नए तरीके तलाश रहा है। इस कड़ी में टीओटी योजना के जरिये तैयार सड़क परियोजनाओं के टोल ठेके देने का उसका कदम नाकाफी साबित हुआ है। लिहाजा, अब वह राजमार्गों के किनारे की जमीन को लीज पर देकर भी पैसा जुटाएगा।

नई चुनौती

टेस्ट सीरीज	सुबह 9:30 बजे से
भारत vs द. अफ्रीका	स्थान : पुणे
	प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

गुलाम कश्मीर से आए सभी परिवारों को सरकार देगी 5.5 लाख रुपये की मदद

कैबिनेट फैसले ▶ केंद्रीय कर्मियों व पेंशनभोगियों को पांच फीसद अतिरिक्त डीए/डीआर का तोहफा

जम्मू-कश्मीर में बसने से पहले दूसरे राज्यों में रहे 5,300 परिवारों को भी मिलेगा लाभ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर से आकर जम्मू एवं कश्मीर में बसने वाले विस्थापित परिवारों के लिए 5.5 लाख रुपये की एकमुश्त मदद का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस दायरे में ऐसे 5,300 परिवारों को भी शामिल किया है, जो गुलाम कश्मीर से आकर पहले किसी अन्य राज्य में रहे थे, फिर जम्मू-कश्मीर में बसे। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। पहले केवल उन परिवारों को मदद का एलान किया गया था, जो गुलाम कश्मीर से आकर सीधे जम्मू-कश्मीर में बसे थे।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट के फैसले का ब्योरा देते हुए कहा, सरकार ने 'ऐतिहासिक गलती' को ठीक कर दिया है। पीएम मोदी ने 2016 में एलान किया था कि विभाजन के बाद अलग-अलग मौकों पर पाक के कब्जे वाले कश्मीर को छोड़कर जम्मू-कश्मीर में आकर बसने वाले परिवारों को सरकार पैकेज देगी। इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया था जो गुलाम कश्मीर से आने के बाद पहले देश के अन्य भागों में रहे और बाद में जम्मू-कश्मीर में बसे।

नई दिल्ली में बुधवार को कैबिनेट के फैसलों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर। प्रेट्र

कब कितने परिवार आए? : वर्ष 1947 में पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से से 31,619 परिवार भारत आए थे। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू-कश्मीर में बस गए थे, जबकि 5,300 परिवार कुछ समय देश के अन्य हिस्सों में रहने के बाद जम्मू-कश्मीर आए थे। वर्ष 1965 और 1971 में भी गुलाम कश्मीर से कुल 10,065 परिवार जम्मू-कश्मीर आकर बसे थे। इन सब विस्थापित परिवारों में से कुल 36,384 परिवारों को 2016 में सरकार की ओर से एकमुश्त पैकेज के लिए चुना गया था। वहीं, देश के अन्य हिस्सों में रहने के बाद जम्मू-कश्मीर आए 5,300 परिवार इससे वंचित रह गए थे।

पांच फीसद अतिरिक्त डीए : सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को पांच फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ता (डीए) तथा पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) देने का फैसला किया है। इससे उनको मिलने वाला कुल डीए/डीआर अब वेतन/पेंशन के 12 फीसद से बढ़कर 17 फीसद हो गया है। इस निर्णय से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी तथा 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। फैसला पहली जुलाई, 2019 से लागू माना जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर सालाना करीब 16,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत फार्मूले के अनुसार की गई है। जावडेकर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा डीए में की गई यह अब तक की सबसे बड़ी एकबारगी वृद्धि है। इससे पहले जनवरी में सरकार ने महंगाई भत्ते को नौ फीसद से बढ़ाकर 12 फीसद किया था। सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का साल में दो बार पुनरीक्षण करती है। पहला पुनरीक्षण एक जनवरी, जबकि दूसरा एक जुलाई से लागू होता है।

'पीएम-किसान' की किस्त मिलने का रास्ता साफ

नई दिल्ली : सभी पंजीकृत किसानों को रबी सीजन से पहले पीएम-किसान योजना की किस्त की राशि दे दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे 1.25 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की किस्त पहुंचने की राह आसान हो गई। चुनावी राज्य हरियाणा व महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों में पीएम किसान योजना के तहत किस्त रुकने से किसानों की नाराजगी सरकार मोल लेना नहीं चाहती है। योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को अपने नाम का पंजीकरण कराने के साथ उसे आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बगैर किसानों को योजना का पैसा न देने का फैसला किया गया था, लेकिन अब कैबिनेट के फैसले में आधार लिंक के प्रावधान को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी पंजीकृत सभी किसानों को पहली, दूसरी या तीसरी, जो भी बकाया किस्त होगी, वह दी जाएगी। जावडेकर ने कहा, रबी सीजन से पहले किसानों को पैसे की सख्त जरूरत होती है, जिसके मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। अब तक सात करोड़ किसानों ने पंजीकरण करा लिया है।

मोदी और चिनफिंग की भेंट में कश्मीर का पेच

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- तमिलनाडु के मामल्लपुरम में 11-12 को दोनों नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता
- अनौपचारिक भेंट में कारोबार और सीमा पर शांति बहाली जैसे गंभीर मुद्दे अहम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच दूसरी अनौपचारिक वार्ता को लेकर बना संशय तो खत्म हो गया है, लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात से ठीक पहले कश्मीर का पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। भारत आने से पहले चिनफिंग की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात और उसमें कश्मीर पर चुभने वाला बयान, उस पर भारत की तल्ख प्रतिक्रिया से साबित हो रहा है कि माहौल पूरी तरह सामान्य नहीं है। वैसे मोदी और चिनफिंग इससे भी ज्यादा तनाव वाले माहौल (डोकलाम घटनाक्रम के बीच) में मुलाकात कर रिश्तों में भरोसा भरने का काम कर चुके हैं।

दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों ने मोदी-चिनफिंग की बहुप्रतीक्षित मुलाकात से दो दिन पहले इसके बारे में आधिकारिक घोषणा की। भारतीय विदेश मंत्रालय और नई दिल्ली में चीन के राजदूत ने कुछ ही मिनटों के अंतराल पर भावी यात्रा का ब्योरा दिया। दोनों पक्षों ने इस बात से इन्कार किया है कि चीन के राष्ट्रपति के दौरे की विलंब से घोषणा के पीछे कोई खास वजह है। इस देरी के बावजूद दोनों पक्षों के बीच इस वार्ता को लेकर तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। चीन के राष्ट्रपति भारत का दौरा समाप्त करने के बाद नेपाल जाएंगे। इस बात के संकेत दिए गए हैं कि दोनों नेताओं की तरफ से अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शांति बहाली के लिए इस बार कुछ और उपायों की घोषणा की जा सकती है। पिछले वर्ष इन दोनों नेताओं के बीच हुई पहली अनौपचारिक वार्ता के बाद इस तरह के उपायों की पहली किस्त की घोषणा की गई थी जिसका सकारात्मक असर देखने को मिला है।

चिनफिंग अपने कई अहम अधिकारियों के साथ शुक्रवार (11 अक्टूबर) को दोपहर में चेन्नई के पास मामल्लपुरम पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात से ही अनौपचारिक वार्ता का दौर शुरू हो जाएगा जो अगले दिन दोपहर तक कई दौर में और कई घंटों तक चलेगी। उनके साथ पोलित ब्यूरो के कुछ बड़े अधिकारी, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी होंगे। इस तरह से मामल्लपुरम में होने वाली दूसरी अनौपचारिक वार्ता वुहान (चीन) में हुई वार्ता से काफी अलग होगी। वैसे बताया गया है कि इस बार भी बिना एजेंडा के बातचीत होगी लेकिन हर अहम मुद्दों को लंबी अवधि के दृष्टिकोण से सुलझाने की कोशिश होगी।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइल फोटो। एपी

राष्ट्रपति चिनफिंग को मोदी देंगे जवाब

जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले को देखते हुए मोदी और चिनफिंग के बीच होने वाली बैठक ज्यादा अहम हो गई है। वामपंथी शासन वाला देश चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले पर सबसे ज्यादा ऐतराज जता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि वैसे तो मामल्लपुरम में दोनों नेताओं की बातचीत में कश्मीर का मुद्दा भारत नहीं उठाएगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति शी चिनफिंग इसका जिक्र करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निश्चित तौर पर उन्हें इसके बारे में विस्तार बताया जाएगा।

बड़े मुद्दों पर स्थायी समाधान की कोशिश

कश्मीर और लद्दाख के पेच को छोड़ दिया जाए तो मोदी और चिनफिंग की कोशिश यही होगी कि द्विपक्षीय रिश्तों के बीच तनाव पैदा करने वाले जो बड़े मुद्दे है उनका स्थायी समाधान निकाला जाए। यही वजह है कि शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली मुलाकात के साथ ही अलग से विदेश मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अलग-अलग बैठक होगी। सीमा पर तनाव को घटाना और द्विपक्षीय कारोबार को लेकर आने वाली दिक्कतों को दूर करना वरीयता में सबसे ऊपर है।

महाबलीपुरम : बेमिसाल शिल्प की नगरी पेज>>5

अब जियो से दूसरे नेटवर्क पर फ्री में नहीं होगी बात

- दूसरे मोबाइल नेटवर्क के लिए छह पैसा प्रति मिनट का शुल्क लेगी कंपनी
- एयरटेल ने कंपनी पर लगाया ट्राई पर दबाव बनाने का आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र : रिलायंस जियो ने वॉयस कॉल के लिए चार्ज लगाने की घोषणा कर दी है। कंपनी अपने नेटवर्क से अन्य नेटवर्क पर की गई कॉल के लिए छह पैसे प्रति मिनट के हिसाब से चार्ज करेगी। नई दरें सभी जियो यूजर के लिए बुधवार से लागू हो चुकी हैं। कॉल टर्मिनेशन चार्ज को लेकर बनी अनिश्चितताओं के चलते कंपनी ने यह कदम उठाया है। हालांकि कंपनी ने इसकी कीमत के बराबर फ्री डाटा देने की बात भी कही है।

जियो ने कहा है कि ये कॉल दरें तब तक लागू रहेंगी जब तक टर्मिनेशन चार्ज पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जाता। हालांकि एक जियो नंबर से दूसरे जियो नंबर तथा किसी भी लैंडलाइन फोन पर की गई कॉल के लिए कोई कंपनी चार्ज नहीं लेगी। एयरटेल ने जियो के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि वह ट्राई को आइयूसी कम करने के लिए बाध्य करना चाहती है।

यह पहली बार होगा, जब जियो के यूजर्स को वॉयस कॉल के लिए कोई शुल्क चुकाना पड़ेगा। इससे पहले जियो सिर्फ डाटा के लिए चार्ज करता था। पूरे देश में किसी भी नेटवर्क पर इसके यूजर मुफ्त में वॉयस कॉल कर सकते थे।

आइयूसी पर फंसा पेच

ट्राई ने वर्ष 2017 में इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज (आइयूसी) को 14 पैसे प्रति मिनट से घटाकर छह पैसे कर दिया था। इस दौरान कहा गया था कि जनवरी, 2020 तक आइयूसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब ट्राई इसकी समय-सीमा बढ़ाने को लेकर विचार कर रहा है। इसके लिए सलाह मांगी गई है, जिसके बाद से आइयूसी को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

रिंगिंग टाइम पर हो चुका विवाद

इससे पहले जियो और उसकी प्रमुख प्रतिस्पर्धी एयरटेल के बीच रिंगिंग टाइम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। एयरटेल ने जियो पर रिंगिंग टाइम कम करने का आरोप लगाया था। इसके बाद 28 सितंबर को एयरटेल ने ट्राई को जानकारी दी थी कि उसने अपना रिंगिंग टाइम 45 सेकेंड से घटाकर 25 सेकेंड कर दिया है। ट्राई 14 अक्टूबर को इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ बैठक करेगा।

जियो का तर्क

दरअसल जियो के नेटवर्क पर कॉल फ्री है, जिसकी वजह से इसे अपने प्रतिस्पर्धी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बीते तीन वर्षों के दौरान 13,500 करोड़ रुपये चुकाने पड़े हैं। अब जियो इसकी भरपाई के लिए अपने ग्राहकों पर चार्ज लगाने जा रही है। इसका कहना है कि जब तक ट्राई टर्मिनेशन चार्ज खत्म नहीं करती, ये दरें लागू रहेंगी।

ये हैं जियो के नए आइयूसी प्लान

- 10 रुपये में 124 आइयूसी मिनट के साथ मिलेगा एक जीबी डाटा
- 20 रुपये के पैक में 249 मिनट और दो जीबी डाटा
- 50 रुपये के पैक में 656 मिनट और पांच जीबी डाटा
- 100 रुपये के पैक में 1,362 मिनट और 10 जीबी डाटा

अभिनेत्री अपर्णा सेन समेत 49 के खिलाफ केस बंद करने का आदेश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

उन्मादी हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने में अभिनेत्री अर्पणा सेन समेत 49 फिल्मी कलाकारों व बुद्धिजीवियों के खिलाफ केस को एसएसपी ने जांच में असत्य पाया है। कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के बाद पर्यवेक्षण रिपोर्ट जारी कर एसएसपी ने केस को बंद करने का निर्देश दिया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा कि आवेदक पर 182/211 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा 27 जुलाई को बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की कोर्ट में दर्ज परिवाद की सुनवाई के बाद सदर थानाध्यक्ष को केस दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। इस मामले में अभिनेत्री सेन के अलावा अडूर गोपाल कृष्णन, शुभा दुग्गल, सुमित्रा चटर्जी, रेवती, कोंकणा सेन, श्याम बेनेगल, मणिरत्म व इतिहासकार रामचंद्र गुहा आदि को आरोपित किया गया था।

यह लगाया गया था आरोप : सुधीर कुमार ओझा ने कहा था कि 23 जुलाई को आरोपित 49 बुद्धिजीवियों ने देश में हो रही उन्मादी हिंसा को लेकर पीएम को पत्र लिखा था। टीवी चैनलों व अखबार में यह बात आई। आरोपितों का यह काम देश की छवि की खराब करने वाला वाला है। प्रधानमंत्री के काम करने की छवि को बदनाम करने की नीयत से यह पत्र लिखा गया है।

एसबीआइ ने लोन और जमा पर ब्याज की दरें घटाईं

मुंबई : देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआइ ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 10 आधार अंकों की कटौती की है। अर्थात बैंक की सभी अवधि की ब्याज दरों में 0.10 फीसद की कटौती होगी। इससे होम, कार व पर्सनल लोन सस्ते होंगे। साथ ही बैंक ने सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज की दर भी 0.25 फीसद तक घटा दी है। इससे बुजुर्गों व पेंशनभोगियों को घाटा हो सकता है। लोन रेट में कटौती की दरें 10 अक्टूबर व सेविंग्स पर ब्याज दरों में कटौती नवंबर की पहली तारीख से लागू होगा। (पेज-12)

राजनयिक मिशनों के जरिये भारत में नकली नोट भेज रहा पाक

लंदन : हर मोर्चे पर भारत से पटखनी खाने के बाद भी पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत में नोटबंदी के तीन साल बाद उसने लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों की फंडिंग के लिए नकली भारतीय मुद्रा को फिर से भारत भेजना शुरू कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस काम के लिए वह नेपाल, बांग्लादेश व अन्य देशों में मौजूद अपने राजनयिक चैनलों का दुरुपयोग कर रहा है। (पेज-13)

राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी कांग्रेस में नहीं थम रहा है घमासान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के सदमे से जूझ रही कांग्रेस का अंदरूनी घमासान थमता नहीं दिख रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि इस समय कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट यह है कि हमारे नेता राहुल गांधी हमें छोड़कर चले गए और सोनिया गांधी भी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में ही काम कर रही हैं। कांग्रेस को संकट से बाहर लाने के लिए मौजूदा हालात की तत्काल समीक्षा की जरूरत है। खुर्शीद ने हरियाणा व महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावनाओं पर खुद ही सवाल खड़े किए।

सलमान खुर्शीद ने कहा, 'हमारा सबसे बड़ा संकट यह है कि हमारे नेता राहुल गांधी इस्तीफा देकर हमें छोड़कर चले गए, जबकि राहुल पर अब भी पार्टी की निष्ठा है और जल्दबाजी में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। पार्टी में हम सभी न केवल चाहते थे बल्कि चाहते हैं कि राहुल अध्यक्ष रहें। तमाम लोगों ने उनसे बार-बार अनुरोध भी किया। वह शायद पहले नेता हैं जिनमें पार्टी नेताओं को दो चुनावों की हार के बाद भी भरोसा था। मगर उनका अपना मत था कि वह अध्यक्ष नहीं रहेंगे। उनके जाने के बाद कांग्रेस में एक तरह का खालीपन है।'

खुर्शीद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी के इस्तीफे से कांग्रेस का संकट बढ़ा है। राहुल के पद छोड़ने के फैसले के कारण कांग्रेस हार के कारणों की अनिवार्य समीक्षा और आत्ममंथन भी नहीं कर पाई। उनका कहना था कि हमें इस पर भी चिंतन करना होगा कि आखिर कांग्रेस इस हालत में कैसे पहुंच गई कि हम न केवल अभी हो रहे विधानसभा चुनावों में, बल्कि अपना सियासी भविष्य तक तय नहीं कर पा रहे। साथ ही कांग्रेस का आधार भी कुछ राज्यों तक सिमट गया है।

सलमान खुर्शीद बोले, राहुल के अचानक जाने से बढ़ा संकट, हालात की हो तत्काल समीक्षा

> सलमान खुर्शीद ने जो कहा है उसका जवाब वही देंगे। पार्टी नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए और एकजुट होकर अपना पूरा दमखम हरियाणा व महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को हराने में लगाना चाहिए।
> -पवन खेड़ा, कांग्रेस प्रवक्ता

सिंधिया बोले, कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत

ग्वालियर : पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि पार्टी वर्तमान में जिन हालात से गुजर रही है, उसमें आत्मचिंतन की जरूरत है। ताकि उस पर क्रियान्वयन कर स्थिति को सुधारा जा सके। उन्होंने कहा कि मैं किसी के वक्तव्य पर कभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा मेरा मानना है।

नसीहत के बाद विस चुनावों पर दिए बयान से पलटे पेज>>3

सम्मान

खोज के करीब पांच दशक बाद ब्रिटेन के वैज्ञानिक स्टेनली विटिंघम को मिला सम्मान, स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक हो रहा लिथियम आयन बैट्रियों का इस्तेमाल

लिथियम आयन बैट्री बनाने वाले वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल

स्टॉकहोम, एएफपी : उपलब्धियां अपने सम्मान का रास्ता बना ही लेती हैं। इस बार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले वैज्ञानिकों की कहानी यही प्रेरणा देती है। 2019 के रसायन नोबेल के लिए अमेरिका के जॉन गुडएनफ, ब्रिटेन के स्टेनली विटिंघम और जापान के अकीरा योशिनो को चुना गया है। तीनों को यह पुरस्कार लिथियम आयन बैट्रियों के निर्माण की दिशा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। उन्हें यह सम्मान अपनी खोजों के 35 से 50 साल बाद मिला है।

लिथियम आयन बैट्रियों ने 1991 में पहली बार बाजार में कदम रखा था। तब से आज तक इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बड़ा बदलाव किया है। आज इन शक्तिशाली, हल्की और रिचार्ज की जा सकने वाली बैट्रियों का इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक में हो रहा है। पिछली सदी के आठवें दशक में विटिंघम ने इसकी नींव रखी थी। बाद में विटिंघम के बनाए रास्ते पर गुडएनफ ने काम आगे बढ़ाया। उनके प्रयोगों ने ज्यादा शक्तिशाली और टिकाऊ बैट्री की उम्मीद पैदा की। 1985 में योशिनो के शोध से वाणिज्यिक तौर पर टिकाऊ बैट्रियां बनाने का रास्ता खुला।

अमेरिका के जॉन गुडएनफ, जापान के अकीरा योशिनो और ब्रिटेन के स्टेनली विटिंघम। रायटर

सबसे उम्रदराज विजेता हैं गुडएनफ

इस साल नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए अमेरिकी रसायन विज्ञानी जॉन गुडएनफ की उम्र 97 साल है। वह नोबेल पाने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक हैं। ब्रिटेन के नागरिक स्टेनली विटिंघम की उम्र 77 साल और जापान के योशिनो की उम्र 71 साल है। पुरस्कार के तौर पर मिलने वाली 90 लाख स्वीडिश क्रोनर (तकरीबन 6.46 करोड़ रुपये) की राशि को तीनों वैज्ञानिकों में बराबर बांटा जाएगा। पिछले साल अमेरिकी वैज्ञानिकों फ्रांसेस अर्नाल्ड व जॉर्ज स्मिथ तथा ब्रिटेन की ग्रेगरी विंटर को एंजाइम के क्षेत्र में शोध के लिए रसायन का नोबेल मिला था। अर्नाल्ड रसायन के क्षेत्र में नोबेल पाने वाली पांचवीं महिला हैं।

आज साहित्य के नोबेल विजेताओं का होगा एलान

इस साल नोबेल विजेताओं के नाम के एलान की शुरुआत सोमवार को चिकित्सा क्षेत्र के विजेताओं से हुई थी। मंगलवार को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल विजेताओं का नाम सामने आया। इस कड़ी में गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीतने वालों का नाम बताया जाएगा। पिछले साल विवाद के चलते स्थगित होने के कारण इस बार 2018 और 2019 दोनों वर्षों के लिए साहित्य का नोबेल दिया जाना है। शुक्रवार को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी। अगले सोमवार को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता के एलान के साथ इस साल के विजेताओं की घोषणा का क्रम पूरा होगा। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम में चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य व अर्थशास्त्र का नोबेल और ओस्लो में शांति का नोबेल दिया जाएगा।

कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में बीडीसी चुनाव के बहिष्कार का किया एलान

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- मीर बोले-प्रशासन ने अटकाए रोड़े, मजबूरी में लिया फैसला
- कश्मीर के हालात, पार्टी नेताओं की नजरबंदी को बताया मुख्य वजह

जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को होने जा रहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल (बीडीसी) के चुनाव के नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन बुधवार को कांग्रेस ने चुनाव बहिष्कार करने का एलान कर दिया। कांग्रेस ने प्रशासन पर रोड़े अटकाने का ठीकरा फोड़ा। पार्टी के प्रदेश प्रधान जीए मीर ने कश्मीर के हालात, पार्टी नेताओं की नजरबंदी, चुनावी तैयारियों का समय न मिलने और कश्मीर जाने की अनुमति न मिलने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी मजबूरी में बीडीसी चुनाव का बहिष्कार कर रही है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों के नेताओं को नजरबंद किया गया। कइयों पर पाबंदियां लगाई गई। ऐसे हालात में क्या बीडीसी के चुनाव संभव हैं, बावजूद इसके कांग्रेस ने भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में नेशनल कांफ्रेंस -कांग्रेस ने ही पंचायतों को मजबूत करने के लिए भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के प्रावधान लागू किए, लेकिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और भाजपा की साझा सरकार ने पंचायतों को कमजोर करने के लिए इसमें संशोधन किया। बाद में कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। पूर्व राज्यपाल एनएन वोहरा ने आदेश को वापस लिया। अभी तक जम्मू कश्मीर में पंचायतों के 12 हजार से अधिक सदस्यों को चुना नहीं गया है। अब भी बीडीसी चुनाव भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत नहीं करवाए जा रहे हैं।

हमारे नेताओं पर पाबंदियां, नहीं जाने दिया जा रहा कश्मीर पेज>>6